

Need to make the Prime Minister Crop Insurance premium free and to provide free seeds to farmers

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): महोदय, भारत कृषि प्रधान देश है। देश की दो-तिहाई से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। देश में हर तीसरे वर्ष किसान सूखा, अकाल, बाढ़ एवं दैवी आपदाओं का शिकार हो रहा है। लगातार तीन वर्षों से बुंदेलखंड विदर्भ का किसान सूखे व अकाल के कारण पलायन एवं आत्महत्या कर रहा है, जिसे रोका जाना आवश्यक है। भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है, जिसकी प्रीमियम एवं शर्तें पूरा करने में किसान असमर्थ है। किसानों को बीजों की समुचित किस्मों की बुआई अथवा खरीद में अतिरिक्त व्यय के लिए बीज की केंद्रीय सहायता की जानी चाहिए, जिससे किसानों को समय से बीज मिल सके और वे साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति पा सकें। देश में ज्यादातर किसान अशिक्षित हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। किसान आर्थिक कमजोरी के कारण भारत द्वारा चलाई जा रही फसल बीमा योजना का प्रीमियम नहीं भर सकता है, इसलिए उसको प्रीमियम मुक्त किया जाना आवश्यक है।

अतः मैं विशेष उल्लेख के माध्यम से प्रधान मंत्री जी से मांग करता हूं कि प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना को प्रीमियम मुक्त किया जाए तथा किसानों को बीजों की समुचित किस्मों की बुआई हेतु बीज मुफ्त प्रदान किये जाये।

Need to improve the Post Office net banking services

श्री लाल सिंह वडोदिया (गुजरात): महोदय, इस वर्ष से देश में हर पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग सेवा भी शुरू की गई है, यह अच्छी बात है। लेकिन वहां सर्वर चालू नहीं रहने की वजह से ग्राहकों की लम्बी लाइन पोस्ट ऑफिस में लग जाती है। दूसरी कठिनाई यह है कि स्टाफ की संख्या पहले ही कम है, लेकिन अब बैंकिंग व्यवस्था शुरू हो जाने के कारण पोस्ट ऑफिस में कर्मचारी कम पड़ने लगे हैं। मेरी जानकारी में आया है कि नियमित रूप से सर्वर में प्रॉब्लम आ जाने के कारण एन.एस.सी. सर्टिफिकेट और केवीपी सर्टिफिकेट टाइम पर नहीं मिल रहे हैं। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि इंटरनेट सेवा के लिए सर्वर नियमित रूप से कार्य करते रहना चाहिए और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में बैंकिंग व्यवस्था चालू हो जाने के कारण अतिरिक्त कर्मचारी भी appoint किए जाएं। पोस्ट ऑफिस में समुचित व्यवस्था न होने के कारण वहां ग्राहकों की लम्बी लाइनें लगी रहती हैं और उनका काम भी देर से होता है, अगर ऐसा किया जाए तो ग्राहकों की तकलीफ दूर हो सकेगी, धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. P. SINGH BADNORE): Shri Punia, not present. Shri Sanjay Raut, not present. Shri Motilal Vohra, not present. Shri Husain Dalwai, not present. Shri Mansuk L. Mandaviya. Shri Vivek Gupta.

Need to release adequate funds for MGNREGA Scheme to all States immediately

SHRI VIVEK GUPTA (West Bengal): Sir, the last financial year came to an end with 24 States facing a total of ₹ 12,483 crores worth of pending payments under NREGA. The pending payments amount to over a quarter of the total expenditure